साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 21-27 फरवरी 2022, वर्ष-7, अंक-47

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-पीएम नरेंद्र मोदी बोले- इंदौर के लोगों ने शहर को भी अच्छा और स्वच्छ बनाया

150 करोड़ रुपए की लागत से बने सीएनजी प्लांट गोबर-धन का किया लोकार्पण

कचरे से 'कंचन'

-इंदौर की प्रेरणा से देश के 75 शहरों में लगाए जाएंगे बायो-सीएनजी प्लांट

-सीएम शिवराज सिंह ने कहा-प्लांट के लिए ग्रामीणों से गोबर खरीदा जाएगा

विशेष संवाददाता,इंदौर।

शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट गोबर-धन के लोकार्पण में ऑनलाइन शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरे को कंचन बनाने के लिए शहर के प्रयासों की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि जितने अच्छे इंदौर के लोग हैं, उन्होंने शहर को भी उतना ही अच्छा बना दिया है। उन्होंने शहर की प्रेरणा से देश के 75 शहरों में बायो-सीएनजी प्लांट बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्लांट से इंदौर को रोज 17 हजार किलो बायो-सीएनजी व 100 टन जैविक खाद मिलेगा। सीएनजी से 400 बसों का संचालन भी होगा। इससे प्रदूषण कम होगा, ग्रीन-जॉब्स बढ़ेंगे।

इंदौर मतलब स्वच्छ

मोदी ने कहा कि इंदौर का नाम आते ही मन में स्वच्छता और नागरिक कर्तव्य का नाम आता है। हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही देवी अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर और उनकी सेवाभाव का नाम आता था। समय के साथ इंदौर बदला है, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को खोने नहीं दिया। यहां के लोग सिर्फ सेंव पसंद नहीं है, बल्कि सेवा पसंद भी हैं।

किसानों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते आठ सालों में पेट्रोलियम उत्पादों में इथेनॉल के मिश्रण का स्तर दो से बढ़ाकर आठ प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। हमारे पास इथेनॉल जैसे जैव ईंधन बनाने के पर्याप्त संसाधन बरसों से उपलब्ध हैं। हमारी सरकार ने जैव ईंधन बनाने की तकनीकी के इस्तेमाल पर खास जोर दिया है। इथेनॉल की खपत बढ़ने से चीनी मिलों की आर्थिक सेहत सुधरी है, गन्ना किसानों को भी खासी मदद मिली है।

स्वच्छता रखना देश की बड़ी सेवा

- इंदौर की बहनों ने छह हिस्सों में बांट कर कूड़ा प्रबंधन को नए मुकाम पर पहुंचाया।
- काशी में देवी अहिल्या की मूर्ति लगाई है। बाबा के साथ लोग उनके भी दर्शन करेंगे।
- पराली की समस्या से निपटने कोयला बिजली घरों में उसका उपयोग होगा।
- सोलर एनर्जी के मामले में देश ने दुनिया में पांचवें नंबर पर जगह बना ली है।
- हमारे पास तेल के कुएं नहीं पर बायो-सीएनजी बनाने के साधन बरसों से हैं।
- अहिल्या की प्रेरणा को खोया नहीं लोग सिर्फ सेंव ही नहीं सेवा भी पसंद करते हैं।
- बायो सीएनजी प्लांट
- 550 टन गीले कचरे से 17500 किलो बायो सीएनजी तैयार
- अगस्त 2020 में शुरु हुआ था निर्माण
- 150 करोड़ रुपये हुए खर्च
- 100 टन प्रतिदिन खाद तैयार होगी
- 15 एकड़ में बना हुआ प्लांट
- 600 टन प्रतिदिन गीले कचरे की कटाई कर सीएनजी बनाने के लिए स्लरी तैयार की जाएगी।
- 4 डाइजेस्ट में स्लरी को डाला जाएगा जिससे बायोगैस तैयार होगी।
- 2 शिफ्ट में सुबह व रात को होगा प्लांट का संचालन।
- 65 कर्मचारी यहां करेंगे काम।
- सेंट्रल कमांड कंट्रोल रुम से प्लांट की होगी मानीटरिंग।
- 400 सिटी बसों को बायो सीएनजी उपलब्ध करवाने की है योजना। उदघाटन के दिन 25 बसों को दिया जाएगा ईंधन।
- 300 किलो बायो सीएनजी अभी हुई है तैयार। रविवार से 500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी और फरवरी माह के अंत तक 2 हजार किलो बायो सीएनजी तैयार होगी।
- एक वर्ष में 200 से ज्यादा बार गीले कचरे की टेस्टिंग कर जांची शुद्धता, यह पता किया गया कि कही सूखा कचरा तो गीले के साथ नहीं आ रहा।
- 96 फीसद मीथेन वाली बायो सीएनजी होगी तैयार।
- 01 लाख 30 हजार टन कार्बन डाई आक्साइड की प्रतिवर्ष बचत होगी।

धरती को मिलेगा जीवनदान

इंदौर के कचरे और पशुधन से गोबर धन और इससे स्वच्छता धन और फिर ऊर्जा धन बनेगा। उन्होंने कहा यह गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट कचरे को कंचन बनाने का काम है। देश के अन्य शहरों और गांवों में भी इस तरह के प्लांट बन रहे है। इससे पशुपालकों को गोबर से आय हो रही है। कचरे से कंचन बनाने के अभियान की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाना चाहिए। यहां बनने वाली जैविक खाद से धरती मां को जीवन दान मिलेगा।

भारत में ड्रोन स्टार्ट-अप का नया कल्चर बन रहा

अब कृषि को मिलेगी नई उडान, 100 'किसान ड्रोन' की मिली सौगात

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों में कीटनाशकों और दूसरे कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 'किसान ड्रोन' का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। अधिकारियों ने इसे किसानों के लिए बेहद नवीन और रोमांचक पहल बताया। मोदी ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्ट-अप का नया कल्चर बन रहा है और जल्द ही ऐसे स्टार्ट-अप्स की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। इनसे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी ड्रोन सेक्टर के विकास में कोई बाधा न हो और इसके ग्रोथ को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले से ही कई सुधार और नीतिगत उपाय किए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि अगर पॉलिसी सही हों, तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। कुछ समय पहले तक ड्रोन ज्यादातक रक्षा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ था।

आधुनिक कृषि सुविधाओं का नया अध्याय

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक नया अध्याय है। इस पहल से न केवल ड्रोन के क्षेत्र में विकास होगा बल्कि इसके लिए अनंत संभावनाओं का भी जन्म होगा। सरकार ने ड्रोन क्षेत्र को खोलने की आशंकाओं पर समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि भारत की युवा प्रतिभा पर भरोसा किया और नई मानसिकता के साथ आगे बढ़ी। सरकार ने बजट और नीतिगत उपायों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है।

2 साल में बनाएंगे 1 लाख ड्रोन

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि गरुड़ एयरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। अभी हाल ही में, बीटिंग रिट्रीट समारोह के माध्यम से 100 ड्रोन दिखाए गए थे।

ड्रोन से पकड़ेंगे मछली

पीएम ने कहा कि किसान ड्रोन एक नई बढ़त क्रांति की शुरुआत करेगा क्योंकि उच्च क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल खेतों से सीधे बाजार तक सब्जियां, फल, मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। इन चीजों को कम से कम नुकसान के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कम समय लगता है, जिससे किसानों और मछुआरों को अतिरिक्त आय होगी।

» देशभर में दूसरे नंबर पर रहा प्रदेश
» 11,716 किसानों ने दिखाई रुचि

औषधीय खेती में मध्यप्रदेश अव्वल

संवाददाता, भोपाल।

आयुर्वेदिक इलाज की पद्धति में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जिन औषधियों पौधों से दवा तैयार होती है, उनकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। औषधीय खेती से किसानों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की ओर से ग्रांट उपलब्ध कराई जाती है। इस मामले में मध्यप्रदेश देशभर में दूसरे नंबर है। यहां औषधीय खेती करने वाले किसानों की संख्या 11 हजार 716 है। देशभर में 59 हजार 350 किसान हैं। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। यहां किसानों की संख्या 12 हजार 859 है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से मप्र टॉप पर

राज्य	भूमि (हेक्टे. में)
मध्यप्रदेश	12,551
उत्तरप्रदेश	12,300
आंध्र प्रदेश	4350
राजस्थान	4113
तमिलनाडू	3931

(लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार)

75 फीसदी तक सब्सिडी

एनएएम योजना के तहत औषधीय की खेती के लिए 15 किमी की परिधि में न्यूनतम 2 हेक्टेयर की भूमि वाले किसानों का समूह बनाने का प्रावधान किया गया। औषधीय खेती के लिए योजना के तहत मध्यप्रदेश में 206 संकुलों को सब्सिडी दी गई। औषधीय खेती को समर्थन देने के लिए 30 से 75 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की गई।

मप्र पहले पायदान पर

आयुष मंत्रालय ने अब तक 84 मेडिसिनल प्लांट के लिए किसानों को सहायता दी गई। वहीं, औषधीय खेती की जागरुकता को लेकर हुए सेमिनार, कार्यशालाओं, क्रेता-विक्रेता की बैठकों के मामले में भी मप्र पहले पायदान पर है। पिछले 64 बड़ी गतिविधियां हुई हैं।

पांच साल में बढ़ा रकबा

मध्यप्रदेश में औषधीय खेती के लिए पांच साल में 2,580 हेक्टेयर क्षेत्रफल का इजाफा हुआ है। वर्ष 2015-16 में 1,681 हेक्टेयर समर्थित क्षेत्र में खेती की गई। वहीं, वर्ष 2020-21 में खेती ब?कर 4,270 हेक्टेयर में हुई। हालांकि बीच के वर्षों में इसमें कमी और बढ़ोतरी भी देखी गई। छह वर्षों में कुल 12 हजार 551 हेक्टेयर क्षेत्र औषधीय खेती के लिए समर्थित रहा।

श्योपुर की 55 पंचायतों में 19 करोड़ से बन रहीं 55 गौशालाएं

पंचायतों में गौशालाएं बन रहीं पर ठीक से नहीं हो रहा संचालन

गौशाला पर खर्च कर दिया करोड़ों फिर भी गायों को नहीं मिला सहारा

संवाददाता, श्योपुर।

बेसहारा गायों और गौवंशों को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा लाखों करोड़ो रुपए खर्च कर ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन गौशाला संचालन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण गायों की सहारा नहीं मिल पा रहा है। श्योपुर जिले की 55 ग्राम पंचायतों में 19 करोड़ की लागत से 55 गौशालाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें से कई गौशाला बनकर तैयार हो गई, लेकिन कई गौशालाओं में ताले लटके हुए हैं। गांवों में घूमने वाली आवरा मवेशी किसानों की फसलों को चौपट कर रही है, जिससे किसान भी परेशान हैं। गायों की देखभाल के लिए सरकार ने भले ही गौशालाएं खोल दी है। इन गौशालाओं को बनाने के लिए लाखों-करोड़ों भी खर्च किए गए हैं, लेकिन फिर भी गौशालाओं में गायों को नहीं रखा जा रहा है।

जिले में 2 लाख 74 हजार 110 गाय

जिले भर में 2 लाख 74 हजार 110 गाय हैं। इनमें से दो लाख 64 हजार 110 गायों को पशु पालक पाल रहे हैं और 10 हजार के निराश्रित होकर सड़कों पर घूम रहीं हैं। जिले भर में 55 गौशालाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। इन गोशालाओं में 5500 गाय रह सकेंगी। इसके बाद 4500 निराश्रित गाय और रह जाएंगी। इनके लिए शासन स्तर से जल्द ही नई गौशालाओं का निर्माण शुरू कराया जाएगा।

31 गौशाला बनकर तैयार

जिले भर के निराश्रित गौवंश को आसरा देने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नरेगा योजना के माध्यम से जिले भर में 55 गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत स्तर पर बनाई जा रहीं गौशालाओं का निर्माण 19 करोड़ 19 लाख 28 हजार रुपए लागत से किया जा रहा है। इनमें से 31 गौशाला बनकर तैयार भी हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही गौशालाए जिनमें मवेशी रखे गए हैं, बाकी गौशालों में ताले लटके हुए हैं।

प्रति गाय पर 20 रुपए होंगे खर्च

गौशालाओं में जिन गायों को रखा जाएगा, उनके लिए शासन स्तर से राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें 15 रुपए चारे पर और 5 रुपए पशु आहार के लिए दिए जाएंगे। इन गायों की देखभाल के लिए प्रत्येक गाय पर रोजाना 20 रुपए का खर्चा किया जा रहा है। फिर भी जिले में बनकर तैयार हुई गौशालाओं में मेसे सिर्फ कुछ ही गौशालों में गायों को रखा गया है।

ददूनी गांव में गौशाला बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें एक भी गाय को नहीं रखा गया है। मेरे खेत में गेहूं की की फसल खड़ी है, कई बार मौका मिलते ही बेसहारा मवेशियों का झुंड फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
मंगल सिंह जाट, निवासी ददूनी

सरकार द्वारा लाखों खर्च कर गौशाला बनाई जा रही हैं। कई ग्राम पंचायतों में गौशाला बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इनका संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे गाय, गौवंश सड़कों पर घूमते रहते हैं। रोड पर मवेशियों के बैठे रहने से कई बार वह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
राजा खान, निवासी कोटरा

जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला बनकर तैयार हो गई है उनमें गायों को रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। बीच में सरपंचों से चार्ज हट गया था। गौशाला में मवेशियों रखने और उनके लिए चारे-पानी व्यवस्था पंचायत द्वारा कराई जाएगी।
सुधीर खांडेकर, सीईओ, जपं, श्योपुर

गिर गाय प्रक्षेत्र बनाने एनडीआरआई की टीम पहुंची श्योपुर

इधर, पिछले दिनों श्योपुर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने गोरस में गिर गाय संरक्षण और प्रक्षेत्र विकसित करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने एनडीआरआई की दो सदस्यीय टीम को श्योपुर भेजा। टीम ने गिर गाय प्रक्षेत्र विकसित करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ गोरस क्षेत्र को देखकर पशुपालकों से भी बात की। टीम ने कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ बैठक कर रूपरेखा तैयार की गई। कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसएस लेठवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गोपाल गोवने ने सबसे पहले गोरस क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके बाद कलेक्टर से बैठक कर गिर प्रक्षेत्र विकसित करने की प्लानिंग की। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में गिर गाय की बहुलता है। गिर नस्ल के संरक्षण की दिशा में क्षेत्र के पशुपालकों को प्रशिक्षित किए जाने की तरूरत है।

आश्वासन के तीन साल बाद भी निराशा

ठंडे बस्ते में आलमपुर गौशाला का निर्माण, नहीं बन पाया डीपीआर

नीरज शर्मा, भिंड। शासकीय अस्पताल के पास गौशाला का निर्माण कराए जाने को लेकर तीन साल पहले जगह चिन्हित की गई थी। साथ ही जमीन का सीमांकन भी किया गया था। नगर परिषद के अधिकारियों ने जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने का आश्वासन दिया था, इसके बाद यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। गौशाला का निर्माण कराया जाना तो दूर अब तक इसकी डीपीआर तैयार नहीं हो सकी है। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गौशाला नहीं है। इस वजह से तीन साल पहले नगर में गौशाला का निर्माण कराए जाने की योजना तैयार की गई। इसके बाद सरकारी अस्पताल मे पास खाली पड़ी 16 बीघा जमीन को गौशाला निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था। इस गौशाला में 500 से 600 गाय रह सकें। इस हिसाब से डिजाइन किया जाना था। राजस्व विभाग की ओर से इस जमीन का सीमांकन किया गया। नगर परिषद के अधिकारियों ने बीते इन दो साल में गौशाला निर्माण के लिए अब तक डीपीआर तैयार नहीं की। हालांकि कई बार सामाजिक संस्थाओं की ओर से नगर में गौशाला निर्माण कराए जाने को लेकर कई बार नप अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

बंद हुई अस्थाई गौशाला

आलमपुर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों की ओर से डेढ़ साल पहले अस्थाई गौशाला शुरू की गई थी। लेकिन वर्तमान में यह अस्थाई गौशाला भी बंद हो गई। नगर में गौशाला नहीं होने की वजह से गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गें तक बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कुछ साल पहले तक नगर में काफी कम मवेशी दिखाई देते थे, लेकिन धीरे-धीरे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

खिरिया में गोचर जमीन पर कब्जा

आलमपुर नगर के राघव नगर खिरिया गांव में 52 साल पहले शासन द्वारा गौवंश के चरने के लिए 80 बीघा शासकीय जमीन को गोचर के लिए तय किया गया था। लेकिन वर्तमान में इस जमीन के करीब 90 प्रतिशत भाग पर दबंग लोग अवैध कब्जा किए हैं। उनके द्वारा गोचर की जमीन जहां पक्के आवास बना लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वे उस पर फसल उगा रहे हैं।

गौशाला का निर्माण अब तक क्यों नहीं हो सका है। इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ से जानकारी ली जाएगी।
विवेक केवी, एसडीएम लहार

-बकरी का दूध पीने के बाद डेंगू नहीं होता था, उसी दौर में लौटना होगा

मुरैना के 14 पशुधन केंद्र से 180 गांवों के हजारों पशुपालक लाभान्वित होंगे

-तोमर बोले-खेती के साथ-साथ पशुधन विकास की अत्यंत आवश्यकता

-गांवों की बढ़गी आय, प्रदेश में पशु नस्ल सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा

अवधेश डंडोतिया, मुरैना।

खेती के साथ-साथ पशुधन विकास की अत्यंत जरूरत है। जिले में 14 पशुधन विकास केंद्र प्रारंभ शुरू किए हैं, जिससे 180 गांवों के हजारों पशुपालक लाभान्वित होंगे। पशुओं की नई नस्लों का विकास होगा। पशुपालन विकसित होता तो गांव की आर्थिक दशा भी सुदृढ़ होगी और प्रदेश में पशु नस्ल सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने हाल ही में बानमोर में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। नाबार्ड और जेके ट्रस्ट द्वारा 9 करोड़ की लागत से 14 पशुधन विकास केंद्र खोले गए हैं। तोमर ने कहा कि डीएपी खाद 1200 रुपए का मिलता है, जबकि सरकार 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। इसलिए हमें कंपोस्ट खाद तैयार करनी होगी। गांव में पशुपालन करेंगे तो हमें विकास की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है। गोबर और गौमूत्र से हम जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते है। पहले हम गांव में गाय, भैंस, बेल, बकरी सभी का पालन करते थे और बकरी का दूध बच्चा पैदा होने पर दिया जाता था। जिससे उसे कभी डेंगू नहीं होता था न उसकी प्लेटें कम होती थीं। आज भी हमारे चिकित्सक डेंगू की प्लेटों के लिए बकरी का दूध बताते हैं। हमें एक बार फिर उसी दौर में आना होगा।

गिर गाय ब्राजील की अर्थव्यवस्था की रीढ़

श्योपुर जिले के गोरस का भी जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि गोरस क्षेत्र में काफी संख्या में गिर नस्ल की गाय हैं। लोग वहां जाकर के सर्वे करें और देखें की सबसे अच्छी गाय की वहां एक नस्ल नई विकसित की जा सकती है। गुजरात में गिर गाय होती हैं अब वहां से ब्राजील चली गई और ब्राजील में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का साधन बन गई है। हमें भी उसकी नस्ल को तैयार करना है तो हम गोरस में एक प्रयास कर ही सकते हैं और पूरे देश में गिर गाय की नस्ल हम चला सकते हैं।

पशुधन का विकास होगा

नाबार्ड अध्यक्ष डॉ. जीआर चिंतला ने नस्ल सुधार में कमी, पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन, दुग्ध मार्केटिंग एवं प्रसंस्करण में कमी और आय में बढ़ोतरी पर कार्य करने की जरूरत बताई। जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि इस योजना से स्व-सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का विकास और कृषि क्षेत्र में पशुधन का विकास होगा। जेके ट्रस्ट के सीईओ राम भटनागर ने कहा कि पूरे राज्य में किसानों की आय बढ़ाने में हमारा ट्रस्ट मदद करेगा। हम सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सहयोगी बनेंगे।

समूह बनाकर बढ़ाई आय

केंद्रीय मंत्री ने पीएमएफबीवाई के बारे में बताते हुए कहा कि लाखों किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। सरकार कृषक समूह बनाकर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रही है। किसान और बाजार के बीच से बिचौलियों-आड़तियों की भूमिका खत्म कर रहे हैं, जिससे किसानों को अनाज का ज्यादा दाम मिले। पिछले पांच सालों में सरकार ने एमएसपी पर खरीद दोगुनी कर दी है। सरकार मोटा अनाज उगाने एवं खरीदने पर जोर दे रही है। फूलों, फलों की खेती को भी आगे बढ़ाने में सरकार पूरा प्रयास कर रही हैं।

कैसे संचालित होती है गौशाला गुरुकुल से लेना चाहिए प्रेरणा

नर्मदापुरम। गौशाला का संचालन कैसे किया जाता है। यह प्राचीन गुरुकुल से सीख लेनी चाहिए। गुरुकुल में 55 गाय हैं। जिसमें करीब दो दर्जन गाय दूध देती हैं। यहां पर हर गाय और उनके बछिया, बछड़े तंदुरूस्त हैं। क्योंकि गुरुकुल में गौवंश का पर्याप्त ध्यान रखा जात है। सभी गाय हस्टपुस्ट हैं। एक गाय 4 से 5 किलो तक दूध देती है। गौशाला में पर्याप्त शेड है। पीने के पानी उचित प्रबंध है। गुरुकुल की भूमि पर हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था है। इतना ही नहीं, गायों के लिए हमेशा पर्याप्त भूसा का प्रबंध रहता है। गुरुकुल से लगी जमीन का कुछ हिस्सा गौशाला संचालन के लिए छोड़ा गया है। गुरुकुल अध्यक्ष स्वामी ऋतस्पति परिब्राजक कहते हैं कि यहां की गौशाला में गाय का पूरा ध्यान रखा जाता। इसमें बडे शेड है ताकि बारिश और धूप से गाय को बचाया जा सके। उनकी खुराक का पूरा इंतजाम रहता है। उन्होंने बताया कि गौशाला में बीमार, दूध नहीं देने वाली और हादसे में घायल हुई गाय की भी सेवा की जाती है। गायों के दूध का सेवन गुरुकुल के ब्रम्हचारियों के द्वारा किया जाता है। गायों के दूध से तैयार घी से हवन किया जाता है। उनके गौमूत्र से औषधी बनाई जाती है। गायों के गोबर से देशी खाद बनाई जाती है। जिन्हें गुरुकुल के बगीचों में डाला जाता है। फसलों में भी देशी खाद का उपयोग किया जाता है।

-शिवराज ने 365 दिनों में 470 से ज्यादा पौधे लगाए

सीएम के 'एक पौधा रोज' संकल्प का एक साल पूरा

संवाददाता, भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वन प्लांट अ डे संकल्प का एक साल पूरा हो गया। 19 फरवरी 2021 को सीएम चौहान ने अमरकंटक में पत्नी साधना सिंह के साथ पौधरोपण कर इस अभियान की शुरुआत की थी। हर दिन एक पौधा लगाने के संकल्प को सीएम चौहान ने हर परिस्थिति में पूरा किया। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वे अपने संकल्प को पूरा करने से पीछे नहीं हटे और होम आइसोलेशन के दौरान सीएम हाउस के गार्डन में नियमित पौधरोपण करते रहे। अपने दौरों के दौरान सीएम प्रदेश के चाहे जिस जिलें में रहें वे वहां पौधारोपण जरूर करते हैं। रोज एक पौधा लगाना सीएम चौहान की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। वह अपने दिन की शुरुआत एक पौधा लगाकर करते हैं। पौधरोपण के 365 दिनों में सीएम चौहान पीपल, बरगद, आम, करंज, नारियल, साल, आवंला, मौलश्री, सप्तपर्णी, गुलमोहर, केसिया, बादाम, देवदार, गूलर, कचनार, अमरूद, बीजा, फाइकस, बकुला के पौधे लगा चुके हैं।

जारी रहेगा अभियान

मुख्यमंत्री ने आने वाले सालों में भी इस अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि पर्यावरण की रक्षा व धरती मां की सेवा के लिए 1 वर्ष पहले 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में मैंने रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पेड़ लगाया था। 19 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2022 तक रोज पौधरोपण करते हुए पूरा एक साल हो गया। कहीं भी रहा पेड़ जरूर लगाए। सीएम ने लिखा कि पौधरोपण के इस अभियान से लोग लगातार जुड़ते चले गए। कई संस्थाओं और समाज के प्रमुख लोगों ने भी मेरे साथ पेड़ लगाए। कम से कम दो पेड़ रोज लगे, कभी-कभी तो कई पेड़ लगे। आज मेरा मन आत्मसंतोष से भरा हुआ है। एक पवित्र काम से लोग जुड़ रहे हैं।

पौधरोपण जरूरी

सीएम ने बाताया कि 19 फरवरी को मैं उन संस्थाओं के साथ भोपाल में पेड़ लगाने वाला था, जिन्होंने मेरे साथ पेड़ लगाए। किन्तु मुझे कोविड होने के कारण अब मैं 24 फरवरी को अपने ऐसे सभी साथियों के साथ पौधरोपण करूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि पेड़ लगाते हुए मैं उनसे एकात्म हो गया हूं। पेड़ मनुष्यों को तो जीवन देते ही हैं, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, कीट-पतंगों को भी आश्रय और जीवन देते हैं। धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने योग्य बनी रहे, इसलिए पौधरोपण जरूरी है। अगले साल भी पौधरोपण का यह अभियान जारी रहेगा। एक नहीं कम से कम दो पेड़ प्रतिदिन लगाएंगे। सीएम ने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि आप भी साथ आइये, हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाइए।

-लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य

संवाददाता, भोपाल।

देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्यों में से एक हैं। देश में सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इस बात का खुलासा हाल ही में लोकसभा में पूछे सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देशभर में 390.6 हजार हेक्टेयर में लहसुन की खेती हुई है, जिससे 3184.8 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 190 हजार हेक्टेयर में लहसुन की खेती हुई है जबकि 1956.7 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। साल 2019-20 में 1837 हजार हेक्टेयर फसल रकबा था और 1869.4 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। इसी तरह 2018-19 178.3 हजार हेक्टेयर से 1821.3 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में साल 2017-18 ऐसा साल था जब मध्यप्रदेश से ज्यादा लहसुन की बोवनी राजस्थान में हुई थी, मप्र में 92.5 हजार हेक्टेयर से 405 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था जबकि राजस्थान में 112.9 हजार हेक्टेयर से 582.1 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2017-18 बेहद कम रेट के चलते राजस्थान में धीरे-धीरे लहसुन का रकबा कम हुआ और साल 2020-21 में 90.9 हजार हेक्टेयर में ही बोवनी हुई है। हालांकि इस साल फिर रेट काफी नीचे हैं।

किसानों को मिल रही सब्सिडी

केंद्र सरकार के मुताबिक वो कुल 25 फसलों (एमएसपी-एफआरपी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। बाकी कुछ फसलों के लिए लहसुन जैसी जल्द खराब होने वाली फसलों को विशेष परिस्थितियों में मंडी हस्तक्षेप योजना के तहत लाभ दिया जाता है। 2017-18 और 2018-19 में राजस्थान के लहसुन किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया। बाकी किसानों को खेती में विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है।

15 राज्यों को दिए 1584.02 लाख

लहसुन की खेती पर अनुदान देश में लहसुन समेत दूसर बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत प्रकंद मसालों के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता देती है। जिसके तहत एक किस्त में किसान को 4 हेक्टेयर तक की खेती के लिए अधिकतम 30000 रुपए या फिर अधिकतम 12000 रुपए प्रति हेक्टेयर 40 फीसदी के हिसाब से सहायता शामिल है। 2018-19 और 2020-21 तक एमआईडीएच योजना के तहत प्रकंद और मसालों के लिए 15 राज्यों को 1584.02 लाख का दिए गए।

यूपी को मिला सबसे ज्यादा फंड

सबसे ज्यादा फंड उत्तर प्रदेश (529.88) को मिला, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ (423.36), तीसरे पर तमिलनाडु (266.76) चौथे पर हरियाणा (162.82) और पांचवें पर केरल (54.89) है। हालांकि नीमच के किसान अरविंद पाटीदार कहते हैं, उन्हें आज तक सिर्फ 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार ने 800 रुपए क्विंटल का भावांतर योजना का लाभ दिया था, क्योंकि उस दौरान लहसुन की कीमत 300 रुपए क्विंटल आ गई थी। बाकी कोई लाभ नहीं मिला, कोई सब्सिडी नहीं मिली।

प्याज की खेती में तीसरे नंबर पर मप्र

अनुसंधान संस्थान प्याज की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है। लहसुन-प्याज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के संस्थान फसल सुधार, फसल उपरांत सुधार आदि पर काम करते हैं। प्याज और लहसुन पर काम के लिए महाराष्ट्र के पुणे के राजगुरुनगर में प्याज और लहसुन निदेशालय है तो बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है।

मप्र में उत्पादन 19 लाख टन से ज्यादा

प्रदेश में इस साल लहसुन के उत्पादन का रिकॉर्ड बन रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में लहसुन का कुल उत्पादन 19 लाख टन के पार होने की उम्मीद जताई गई है। मप्र, राजस्थान, उप्र, गुजरात, पंजाब और असम को प्रमुख लहसुन उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। इसमें मप्र सबसे ज्यादा लहसुन उगाता है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार 2020-2021 में राज्य सरकार ने प्रदेश में 19.66 लाख टन लहसुन का उत्पादन आंकलित किया है। जबकि केंद्र ने मप्र में 19.57 लाख टन लहसुन का उत्पादन होने का अनुमान जताया है।

पिछले 20 वर्षों में क्रॉपिंग पैटर्न बदला है। अब किसान इंफॉर्मेशन तकनीकी का यूज कर रहे हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर दूसरे जगहों के वीडियो देखकर खेती कर करते हैं। ऐसे जब कई बार किसान दूसरों की देखा देखी या एक साल रेट ज्यादा होने पर उसी फसल की बंपर बोवनी करते हैं तो रेट गिर गाते हैं। ऐसे जब तक क्रॉप बजटिंग पूरे देश में सही तरीके से नहीं होगी ऐसा होता रहेगा। कभी कोई चीज काफी महंगी हो जाती है कभी रेट गिर जाते हैं।

आशीष कनेश, उज्जैन मंडल के संयुक्त निदेशक बागवानी (प्रभारी)

इस साल रेट बहुत कम रहा। हमारा लहसुन 500 से लेकर 900 रुपए कुंटल में थोक में गया यानी औसत भाव 700 का रहा, जबकि लहसुन की औसत लागत की 2500-3000 रुपए कुंटल आती है। लहसुन का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, बल्कि पूरी मालवा बेल्ट और एमपी से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ में खूब लहसुन होता है। राजस्थान में कोटा और अलवर में बड़े पैमाने पर लहसुन प्याज की खेती होती है।

अरविंद पाटीदार, किसान, नीमच

-बुंदेलखंड में कच्चे मकान का सरकार देगी 50 हजार मुआवजा

-पक्के घर का 1.50 और आधा कच्चा-पक्का का 1 लाख राहत

केन-बेतवा से मप्र के 10 गांव के दो हजार घर होंगे प्रभावित

संवाददाता, भोपाल।

केन नदी को बेतवा से जोड़ने के लिए मप्र के बुंदेलखंड के ढोढ़न में बनाए जा रहे मुख्य बांध के डूब क्षेत्र में दस गांव आ रहे हैं। परियोजना के मुख्य बांध से बिजावर तहसील इलाके के बसौदा, भरकुआं, ढोढ़न, घौरारी, खरयानी, कुपी, मैनारी, पलकोंहा, शाहपुरा और सुकवांहा गांव के 1913 घर और 8 हजार 339 लोग बांध से प्रभावित होंगे। वहीं बांध बन जाने से छह जिलों छतरपुर, पन्ना, झांसी, महोबा, टीकमगढ़, बांदा के 62 गांव के 2480 किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रारंभिक डीपीआर के मुताबिक 637 कच्चे घर, 1252 आधे कच्चे-पक्के मकान, और 24 पक्के मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रभावित घरों के मालिकों को मुआवजा के बतौर पक्के मकान के बदले डेढ लाख, आधा कच्चा-पक्का मकान का एक लाख और कच्चा मकान का 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दस गांव के डूब क्षेत्र में जाने से न केवल वहां के लोग, बल्कि पालतू मवेशी भी प्रभावित होंगे। 9317 गाय, 249 भैंसा, 3387 भैंसे, 345 भेड़, 11957 बकरी, 1378 मुर्गा-मुर्गी और 1952 अन्य पालूत जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं।

खेती पर पड़ेगा असर

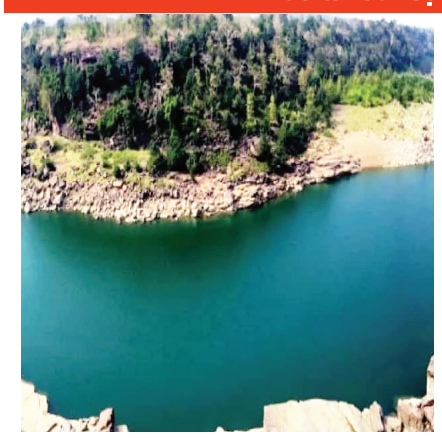

बांध के कमांड क्षेत्र में चयनित परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चयनित परिवारों के विभिन्न फसलों खरीफ सीजन में 2665 हेक्टेयर और रबी सीजन में 1173 हेक्टेयर में खेती होती है। खरीफ मौसम के दौरान सबसे अहम फसल सोयाबीन है जिसका क्षेत्रफल 685.69 हेक्टेयर है। खरीफ मौसम के दौरान उगाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण फसलें बंगाल चना 677.06 हेक्टेयर, धान 669.53 हेक्टेयर हैं, जबकि काला चना, तिल, मिर्च और ज्वार भी उगाई जाती है। वहीं, रबी सीजन के दौरान गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है जिसका क्षेत्रफल 890.85 हेक्टेयर है। इसके बाद बंगाल चना, ज्वार, धान, गन्ना और मक्का भी उगाया जाता है।

मप्र और यूपी के बुंदेलखंड अंचल में पेयजल और सिंचाई का संकट जग जाहिर रहा है। यहां के रहवासियों को जीवन निर्वहन के लिए पलायन करने पर मजबूर करती है। प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देते हुए एक नए विकसित बुंदेलखंड की परिकल्पना को साकार करने का कदम बढ़ाया है।

गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री

केन-बेतवा लिंक परियोजना, बुन्देलखण्ड में विकास की नई उड़ान

गोपाल भर्गव
मप्र के लोक निर्माण विभाग के मंत्री

मप्र और उप्र के बुन्देलखण्ड अंचल में लम्बे अरसे से पेयजल और सिंचाई का संकट जग जाहिर रहा है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र देश में आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इ क्षेत्र का अधिकांश भूभाग पथरीला है और सिंचाई के लिए पानी की कमी यहां के मेहनतकश रहवासियों को जीवन निर्वहन के लिये पलायन करने पर मजबूर करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र को केन-बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देते हुए एक नये विकसित बुन्देलखण्ड की परिकल्पना को साकार करने का महत्वाकांक्षी कदम बढ़ाया है। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करते हुए बुन्देलखण्ड अंचल की तकदीर और तस्वीर बदलकर विकास की नई उड़ान भरेगी।

लगभग 23733 वर्ग किलोमीटर में फैले बुन्देलखण्ड अंचल में बेतवा-केन नदियों को जीवन-रेखा कहा जाता है। इनके साथ ही धसान, सिंध (काली सिंध) नमज़्दा का प्रवाह भी अंचल की आर्थिक समृद्धि में सहायक है।

इस सब के बाबजूद बुन्देलखण्ड अंचल में पानी की गंभीर समस्या रही है। यही कारण रहा होगा कि अंचल में राजशाही के समय बड़ी संख्या में बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण कराया गया, लेकिन घटती वर्षा और बढ़ते शहरीकरण से इन तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप सूखी खेती के साथ पेयजल समस्या ने भी विकराल रूप ले लिया।

देश में अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका ध्यान बुंदेलखण्ड की इस समस्या पर गया। उन्होंने यह समझ लिया था कि पलायन रोकने और बुंदेलखण्ड के विकास के लिये यहाँ की पानी की समस्या को खत्म करना बेहद जरूरी है। इसीलिये अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 में उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना की परिकल्पना तैयार करवाई। इसके जरिए उनका उद्देश्य बुंदेलखण्ड की दो बड़ी नदी केन एवं बेतवा को आपस में जोड़कर बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकना था, ताकि बारिश के पानी का संग्रहण और सही उपयोग हो और प्यासा बुंदेलखण्ड हरियाली से भरा क्षेत्र बन पाये। स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद देश में कई सरकारें केन्द्र में आई और गई, मगर बुंदेलखण्ड की इस समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर जब

भाजपा सरकार बहुमत के साथ केन्द्र में आई, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिर से अटल जी के इस सपने को पूरा करने की ठानी। काफी समय तक यह परियोजना पानी बंटवारे के विवाद के चलते उलझी रही। करीब 19 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पिछले वषज़ 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से दोनों प्रदेश पानी बंटवारे पर सहमत हुए। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए देश के अलग-अलग क्षेत्रों में नदियों को एक करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय बजट में पास किया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा विशेष रूप से केन-बेतवा नदियों को लिंक करने के लिये 44 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार खर्च करेगी। शेष दस फीसदी मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी। हम लोग पुराने समय से देखते आये हैं कि कई बार पानी के अभाव में बुंदेलखण्ड के किसानों को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अब प्रधानमंत्री श्री मोदी का बुंदेलखण्ड के विकास पर विशेष ध्यान होने से स्वीकृत हुई केन-बेतवा लिंक परियोजना किसानों के जीवन और खेती में बदलाव लायेगी। इस योजना पर करीब 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिये इस परियोजना से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगीरथ के समान कार्य किया है, जिससे बुंदेलखण्ड का विकास और अधिक तेजी से होगा। अब बुंदेलखण्ड के खेतों में और अधिक हरियाली आयेगी और गर्मी के मौसम में भी खेतिहर मजदूरों को रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं। वही उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। इस पूरी योजना से इन सभी जिलों को पेयजल के साथ सिंचाई में लाभ होगा, जिससे करीब साढ़े नौ लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। उनका

मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण को बनाया जन-सामान्य की आदत

संदीप कपूर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 19 फरवरी 2022 को प्रतिदिन पौध-रोपण करते हुए एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन पौध-रोपण का संकल्प लिया था। इस अवधि में 490 पौधे रोपे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया है कि - पेड़ मनुष्यों को तो जीवन देते ही हैं, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, कीट-पतंगों को भी आश्रय और जीवन देते हैं। धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने योग्य बनी रहे, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है। अगले साल भी वृक्षारोपण का यह अभियान जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से पृथ्वी तथा आगामी पीढ़ियों को बचाने के लिए पौध-रोपण को सबसे सरल और सभी के द्वारा की जाने वाली गतिविधि मानते हैं। इस पुनीत कार्य में जन-जन के सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण-संरक्षण और स्वच्छता की गतिविधियों में योगदान देने वाले व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जन-सामान्य को अपने परिजन की स्मृति में, परिवार के सदस्यों और मित्रों के जन्म-दिवस तथा अन्य शुभ अवसरों पर भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं।

प्रदेश के अतिरिक्त आठ राज्यों में लगाए पौधे: मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में हो, प्रदेश में कहीं प्रवास पर हों या प्रदेश के बाहर कहीं भी यात्रा में हों, उन्होंने प्रतिदिन पौधा अवश्य लगाया है। अमरकंटक से आरंभ किए गए पौध-रोपण अभियान में भोपाल के स्मार्ट उद्यान, मुख्यमंत्री निवास, मिंटो हॉल परिसर, सुशासन संस्थान, भदभदा विश्राम घाट, मंत्रालय परिसर, शौर्य स्मारक, सहित प्रदेश में होशंगाबाद, नसरुल्लागंज, जबलपुर, पचमढ़ी, इन्दौर, विदिशा, बोरी, पन्ना, बुरहानपुर, सतना, उज्जैन आदि स्थानों पर पौध-रोपण किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पश्चिम बंगाल के जगतबल्लवपुर, भरूच गुजरात स्थित मनन आश्रम, दिल्ली, मुम्बई, तमिलनाडु के गौड़ा देवी मंदिर परिसर, हरिहर आश्रम कनखल हरिद्वार, कम्पनी बाग वाराणसी, शिरडी धाम, नासिक और हैदराबाद के जियर स्वामी आश्रम में भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरिद्वार प्रवास के दौरान स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी परमानंद गिरि जी तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पौध-रोपण किया।

जन-जन को शामिल किया पौध-रोपण में: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पौध-रोपण में जन-जन को शामिल किया। नवम्बर माह में प्रदेश के स्थापना दिवस पर अपनी प्रस्तुति देने आए पार्श्व गायक श्री मोहित चौहान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ पौधा लगाया। इसी क्रम में खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा के जन्म-दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा वी.डी. शर्मा द्वारा पौध-रोपण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सामान्य व्यक्तियों को भी पौध-रोपण में शामिल किया। खुशीलाल प्रजापति, लखन प्रजापति, शिवानी प्रजापति जैसे माटी शिल्पकार हों या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में समय-सीमा में ऋण चुकाने वाले अशोक राठौर, वृंदावन चौरसिया और इमाम खान या फिर नगर निगम के साथ कार्य कर रहे स्वच्छता मित्र या वृक्षारोपण के लिए अंकुर अभियान से जुड़े अंकुर मित्र हों, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज के लिए बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के साथ पौध-रोपण किया।

समाज के लिए मिसाल बने लोगों को भी जोड़ा पौध-रोपण से: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोगों को पौध-रोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों के साथ भी पौध-रोपण किया, जो समाज के लिए मिसाल हैं। इनमें इंदौर की यू-ट्यूबर कुमारी खनक हजेला, भील चित्रकार पद्मश्री भूरी बाई, पद्मश्री डॉ. कपिल तिवारी, प्रख्यात अभिनेता राजीव वमाज़, प्रसिद्ध शायर मंजर भोपाली, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए देश की सायकिल यात्रा पर निकले कर्नाटक के धनुष एम और हेमंत वायबी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रसिद्ध पर्वतारोही अंजना यादव, गौ-काष्ठ के उपयोग के प्रचार-प्रसार में लगे पर्यावरण वैज्ञानिक योगेंद्र सक्सेना, पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही आशी चौहान और नरेश बग्गन तथा प्रदेश के पहले एवरेस्ट विजेता भगवान सिंह शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर की स्मृति में 7 फरवरी को भोपाल की ख्यातिनाम संगीत विभूतियों के साथ पौध-रोपण किया। इसी प्रकार विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को भोपाल में संचालित समस्त एफएम. रेडियो के रेडियो जॉकी के साथ पौध-रोपण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बच्चों में पौध-रोपण की प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से बाल साहित्य सृजन के लिए समर्पित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केन्द्र के सदस्यों के साथ भी पौध-रोपण किया गया।

स्थानीय प्रजातियों और परिवेश के अनुरूप पौध-रोपण को किया प्रोत्साहित: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सवज़्प्रथम 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में गुलबकावली और साल का पौधा लगाया। इस पौधों को रोपने का संदेश यही था कि पौध-रोपण में स्थानीय प्रजातियों और परिवेश के अनुरूप पौध-रोपण को प्रोत्साहित किया जाए। उल्लेखनीय है कि अमरकंटक क्षेत्र में साल की बहुतायत है, साथ ही गुलबकावली का पौधा दुर्लभ प्रजाति का है। यह अमरकंटक में सामान्यत: पाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पौध-रोपण के क्रम में पारिजात, सप्तपर्णी, अशोक, करंज, शीशम, वट वृक्ष, पीपल, कदम्ब, नीम, हरसिंगार, गूलर, बेल पत्र, रूद्राक्ष, चंदन, चाँदनी, अगर, मौलश्री, चम्पा, गुलमोहर, मुनगा, शमी, अरीठा, कचनार, हरज़, मधुकामिनी, केसिया, अर्जुन, हल्दू, पिथोरिया, नवल श्री, खेजड़ी, बीजा, देवदार के पौधे लगाए। इस क्रम में फलदार वृक्षों के पौधे जैसे आम, चीकू, अमरूद, आँवला, नारियल, संतरा, सीताफल, जामुन, खिरनी, लीची के पौधे भी रोपे गए।

आरंभ किया प्रदेशव्यापी अंकुर अभियान: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जन-भागादारी से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस - 5 जून 2021 को प्रदेशव्यापी अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें वायुदूत एप भी लांच किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को एप पर रजिस्ट्रेशन कराकर स्वयं के द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है। लगाए गए पौधे की एक माह बाद पुन: फोटो अपलोड की जाना है। इनमें से चयनित प्रतिभागियों को प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

लेखक मप्र जनसंपर्क के अधिकारी हैं

किसान कृषि पैटर्न में बदलाव से करें खेती का सर्वांगीण विकास

राहुल उपाध्याय

राहुल उपाध्याय
स्वतंत्र पत्रकार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां कुल आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा गांवों में निवास करती है, जिसमें 80 से 90 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। देश में कृषि परंपरागत रूप में की जाती रही है और परंपरागत कृषि खेती करने का एक पुराना तरीका है।

भारत में भौगोलिक विषमता पाई जाती है। यहां पर कहीं उंचे पहाड़, पठार, पर्वत, पथरीली जमीन और कम उपजाऊ जमीन सहित कई अन्य विषमताएं पाई जाती हैं। इस वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में ठीक ढंग से खेती नहीं हो पाती है। जैसे कि किसी राज्य में यदि धान की अधिक पैदावार होती है तो गेहूं की कम, यदि गेहूं अधिक पैदा होता है तो धान कम। कुछ इन तरीकों को अपनाकर कृषि का विकास किया जा सकता है।

क्रॉप पैटर्न में बदलाव: बेहद जरूरी है कि किसानों को अपने क्रॉप पैटर्न यानी बीज की बुवाई में बदलाव करते रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, भारत में ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते चले आए हैं। जैसे कि जब धान की रोपाई होती है तो वे धान की ही रोपाई करेंगे और जब गेहूं की बुवाई होती है तो वे गेहूं की ही बुवाई करेंगे। ऐसे में यदि देखा जाए तो यह बहुत बड़ा कारण है, कृषि विकास न होने का। इसमें सुधार की बेहद आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम पपीते की खेती करते हैं तो उसके साथ हल्दी या अदरक जैसी अन्य फसलों को भी खेती कर सकते हैं। किसानों को कृषि करने के नए-नए तरीके और आधुनिकीकरण से रूबरू होना चाहिए।

कृषि में नवाचार: भारत के ज्यादातर खेत गेहूं और धान की खेती को समर्पित हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में धान और गेहूं की एकल फसल उगाने वाले किसानों को इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। आज फसलों में विविधता लाने से खेती में ज्यादा लाभ संभव है। विशेष रूप से लघु और सीमांत कृषक सब्जियां और फल उगाकर तथा पशुपालन से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसान धान की खेती करते हैं तो उसमें वे मछली पालन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसी खेती चीन और जापान जैसे देशों में की जा रही है।

एमएसपी कानून बने: एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों की ओर से बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीद करने के लिए तैयार रहती है। एमएसपी की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर साल में दो बार रबी और खरीफके मौसम में की जाती है। किसी फसल की एमएसपी इसलिए तय की जाती है, ताकि किसानों को किसी हालत में जो न्यूनतम दर निर्धारित की गई है, वो मिलती रहे।

स्टोरेज की व्यवस्था: किसानों के लिए स्टोरेज यानी भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि देश में खेती करने की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में सहकारिता विभाग को यह चाहिए कि वह पंचायत की जमीन पर भंडारण की व्यवस्था करे। इससे यह फायदा होगा कि किसानों को भंडारण के लिए प्राइवेट भंडारण गृह में नहीं जाना पड़ेगा और किसान कई तरह की समस्याओं से बचा रहेगा।

-मप्र, यूपी, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में भी जा रही फसल,-किसानों ने उत्पादन के कारण बनाई अपनी पहचान

'स्वीट कॉर्न' बना छिंदवाड़ा के कई गांवों की पहचान

-किसान आठ साल में मीठे मक्का की कर रहे खेती

दयानंद चौरसिया, छिंदवाड़ा।

सरकारें हमेशा से ही खेती को फायदे का धंधा बनाने के दावे करती रही हैं। गाहे बगाहे इस दावे को सच साबित करने वाली तस्वीर भी सामने आती रहती है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले से सामने आई है। यहां के कई गांव भी खेती की उजली तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन गांव ने स्वीट कार्न के उत्पादन के कारण अपनी नई पहचान बनाई है। इन गांवों को स्वीट कार्न विलेज के तौर पर पहचाना जाने लगा है। छिंदवाड़ा वह जिला है जहां मक्का की पैदावार तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, मगर बीते सात-आठ साल में यहां के किसानों ने मीठा मक्का अर्थात स्वीट कार्न को अपनाया। इसके चलते बड़ा बदलाव आया है। बीते एक दशक ने यहां के किसानों के खेती के तरीके के साथ आमदनी में बड़ा बदलाव लाया है। बीजकवाड़ा की बात करें तो यहां वर्तमान मे 160 हेक्टेयर क्षेत्र में 36 किसान स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। इस साल इन किसानों ने लगभग 2400 मीट्रिक टन स्वीट कॉर्न का उत्पादन किया, जिससे उन्हें तीन करोड़ 60 लाख रुपए की आय हुई है।

शिक्षक से बन गए प्रगतिशील किसान

बीजकवाड़ा के बड़े किसान और गांव को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गुरु प्रसाद पवार कभी शिक्षक हुआ करते थे, मगर अब जागरुक और प्रगतिशील किसान के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में खेती करते है, इसमें तीन फसल लेते है एक फसल स्वीट कार्न की है। आखिर यह फसल की पैदावार कैसे शुरू हुई, इस पर पवार का कहना है कि वर्ष 2013-14 में कृषि विभाग ने स्वीट कार्न की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और अब उनकी आय पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। आसपास के कई गांव के किसान भी स्वीट कॉर्न की खेती करने लगे है।

अब नुकसान कम, फायदा ज्यादा

गुरु प्रसाद पवार का कहना है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा तो दिलाएंगे मगर नौकरी न कराने का इरादा है, इसकी वजह है क्योंकि खेती से उनकी इतनी आमदनी होगी जितना पैकेज कोई कंपनी उन्हें आसानी से नहीं देगी। छवाड़ी कलां के किसान नारद पवार की जिंदगी में भी स्वीट कार्न की खेती ने बड़ा बदलाव लाया है। वे बताते हैं कि उनके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में स्वीट कार्न की खेती होती है, वे पहले देशी मक्का की खेती करते थे, जिसमें उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा होता था।

अन्य किसानों का बढ़ा रुझान

नारद पवार स्वीट कार्न की खेती के लिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रशिक्षण लिया और धीरे-धीरे इसे अपनाया, वर्तमान में 15 एकड़ में स्वीट कार्न की खेती कर रहे है, जिससे प्रति एकड़ 40 हजार शुद्ध मुनाफा हो जाता है। छिंदवाड़ा के कई गांव में किसान इस फसल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ने के साथ जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में सफल हो रहे हैं तो वहीं अन्य जरुरतों को आसानी से पूरा कर पा रहे है।

परासिया विकासखंड के उमरेठ क्षेत्र के दस गांव के 500 किसान एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीट कार्न की खेती कर रहे हैं। यह जागरुक और प्रगतिशील किसान हैं, जो साल में तीन फसल आलू, तरबूज और स्वीट कार्न की फसल लेकर अच्छा खासा फायदा पा रहे हैं। स्वीट कार्न विलेज के तौर पर खास पहचान बनाते गांव में से एक है बीजकवाड़ा। इस गांव में बड़ी संख्या में किसान देशी मक्का की खेती करते रहे हैं।

जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक, कृषि विभाग, छिंदवाड़ा

-किसानों से की चर्चा और दिए सुझाव

अफसरों ने प्राकृतिक खेती का किया अवलोकन

छिंदवाड़ा। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिले के विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम खैरवाड़ा व बिंदरई और विकासखंड छिंदवाड़ा के ग्राम गुरैया में किसानों के खेतों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र के सह संचालक डॉ. वीके पराडकर, कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एसके पन्नासे, सहायक संचालक कृषि दीपक चौरसिया और अनुविभागीय कृषि अधिकारी छिंदवाड़ा नीलकंठ पटवारी साथ में थे। उप संचालक कृषि ने बताया कि विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम खैरवाडा में उन्नातशील युवा कृषक देवेश बारसकर के खेत का भ्रमण कर उसके द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन किया गया। कृषक द्वारा ड्रिप पद्धति से 2 एकड़ में उटी किस्म की लहसुन और मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करते हुए 5 एकड़ में गेहूं की फसल ली गई है। किसान ने बताया कि मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करने से 60 से 70 प्रतिशत पानी की बचत एवं लागत में कमी के साथ ही परंपरागत सिंचाई पद्धति की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

-जीआई टैग मिलने के बाद चावल की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर तक

चिन्नौर चावल उत्पादक किसानों का बढ़ा लाभ

बालाघाट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी जिसे जिले के चिन्नौर उत्पादक किसानों ने सच कर दिखाया है। जिले के सुप्रसिद्ध चिन्नौर चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है जिसके कारण जिले के चिन्नौर चावल की ख्याति राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। चिन्नौर की चावल की बाजार में बढ़ती मांग के कारण जिले के चिन्नौर उत्पादक कृषकों को उनकी उपज के अच्छे भाव मिल रहे है। जिले में चिन्नौर धान 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। खरीफ वर्ष 2021 में किसानों को चिन्नौर का प्रति एकड़ 8.10 क्विंटल का औसत उत्पादन मिला। इस प्रकार चिन्नौर की खेती से किसानों को प्रति एकड़ 52000 रुपए की औसतन आय हुई वहीं मोटे धान का 18 क्विंटल प्रति एकड़ औसत उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए के हिसाब से प्रति एकड़ 34920 रुपए की आय हुई।

हो रहे आत्मनिर्भर

वर्तमान में व्यापारियों के अलावा केंद्र पोषित योजना द्वारा गठित वारासिवनी विकासखंड के चिन्नौर वैली एफपीओ और लालबर्रा विकासखंड के लालबर्रा चिन्नौर एफपीओ भी बड़े स्तर पर चिन्नौर धान की खरीदी कर रहे है। अब ये दोनों एफपीओ अन्य विकासखंडों के चिन्नौर उत्पादक किसानों से चिन्नौर खरीद रहे है।

-20 लाख टन उत्पादन की संभावना, करोड़ों का होगा कारोबार

मालवा का चमकदार गेहूं विदेश में भी बिखेरेगा अपनी चमक

वंदना बृजेश परमार, उज्जैन।

मौसम की अनुकूलता व सब कुछ ठीक रहा तो इस बार मालवा का गेहूं देश के महानगरों के साथ सात समंदर पार भी चमकेगा। जिले में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की गई है, जो पकने की तैयारी में है। एक सप्ताह मे चमकीला गेहूं कृषि मंडियों में बिकने लगेगा। उत्पादन करीब 20 लाख टन का आंका जा रहा है। यहां का गेहूं देश विदेश की पहली पसंद मानी जाती है। बीते दो वर्ष से कोरोना के चलते पिछड़ रहा गेहूं का कारोबार इस वर्ष गति पकड़ने की दिशा में अग्रसर दिखाई दे रहा है। मालवा की माटी में गेहूं की लहलहाती फसल पकने को तैयार है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बोया गया है। उत्पादन करीब 20 लाख टन होने की संभावना है। पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण होने से मालवा का गेहूं व आटा देश के महानगरों के साथ अब निर्यात भी होने लगा है। करोड़ों का कारोबार के चलते कारोबारी मालामाल होंगे। वहीं, किसानों को भी अधिक भाव मिलेगा।

प्रोटीन के कारण पहली पसंद

उद्योगपति व कारोबारी नितिन शाह बताते हैं कि मालवा के गेहूं में मिठास के साथ प्रोटीन व ग्लूटोन की मात्रा अधिक होने के कारण श्रीलंका, दुबई, अरब देशों से लेकर अमेरिका, रूस तक मे पसंद किया जाता है। कांडला पोर्ट से करोड़ों रुपये का गेहूं विदेशों के लिये जहाज में लदान होता है। बीते दो सालों से कोरोना के कारण व्यापार कमजोर हो गया था। इस बार जबरदस्त मांग की आशा है।

मंडी में 10 शार्टेक्स मशीनें

उज्जैन मंडी में करीब 10 शार्टेक्स मशीनें हैं जहां पर गेहूं शार्टेक्स होकर चमक के साथ बोल्ड दाना बन जाता है। यहां के शरबती गेहूं के भाव काफी अकल्पनीय होते हैं। यह मंडी नीलामी में ही 4000 रुपए क्विंटल बिक जाता है। इस बार किसानों ने लोकवन, पूर्णा के अतिरिक्त पोषक मालव राज किस्म का गेहूं भी काफी बोया है जो कि दलिया, पास्ता, लापसी जैसे अनेक व्यंजन बनाने में काम आता है।

हरदा में मूंग की बंपर पैदावार से बढ़ी किसानों की आय

हरदा। जले के ग्राम पानतलाई निवासी सुशील पिता संतोष कुमार ग्रेजुएट किसान हैं। अपनी 9 एकड़ जमीन में प्राकृतिक व जैविक पद्धति से खेती कर सुशील ने अच्छी आय प्राप्त की है। सुशील ने खेत के मेड के अगल-बगल 30 से 40 पेड़ लगाए हैं जिनमें अम्रपाली, दशहरी, चीकू, अमरुद, आलूबुखारा, चेरी आदि के पेड़ हैं जो पूर्ण रूप से जैविक खाद गौमूत्र आदि डालकर तैयार किए गए हैं। जिनसे मुझे 70 से 80 हजार का उत्पादन वार्षिक प्राप्त हो जाता है। सुशील ने बताया कि उसके द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज कृषि विभाग से लेकर मूंग उत्पादन किया। मूंग की खेती के दौरान वर्मी कंपोस्ट एवं डी कंपोजर का प्रयोग किया। कीटनाशक में नीम तेल एवं मेरे द्वारा बनाए गए नीम अस्त्र पत्तियों के अर्क का प्रयोग किया। नींदाई मजदूरों से कराई गई, दो पानी उगाने के बाद दिए, इस प्रकार कम खर्च में 65 दिन बाद मैंने कटाई कर प्रति एकड़ 13.28 क्विंटल मूंग शुद्ध प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 116.60 क्विंटल प्राप्त किया जिसको मैंने समर्थन मूल्य पर एवं मंडी में बेचा जिससे मुझे कुल 678346 रुपए शुद्ध प्राप्त हुए हैं। इससे मैंने एक हार्वेस्टर मलकीत कंपनी का बुक किया और अगस्त माह में हार्वेस्टर ले लिया। गांव के अन्य खेतों में हार्वेस्टर किराए से देकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर लेता है।

-2021-22 में देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान का अनुमान

गेहूं चावल से भरे रहेंगे अनाज के गोदाम

भोपाल/नई दिल्ली।

कोरोना की तीसरी लहर से उबर रहे देश के लिए अच्छी खबर है। देश में साल 2021-22 में रिकॉर्ड खाद्यान्न अनुमान होने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में धान, गेहूं, तिलहन, दलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। 2021-22 में 316.06 मिलियन टन खाद्यान होने का अनुमान है जो कि साल 2020-21 के 310.74 मिलियन टन से 5.32 मिलियन टन ज्यादा है। साल 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान के हवाले से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रमुख फसलों का इस साल रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। देश में खरीफ और रबी सीजन को मिलाकर देश में 127.93 मिलियन टन चावल होने का अनुमान है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2020-21 में 124.37 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। वहीं देश की दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। चावल की अपेक्षा गेहूं कम राज्यों में उगाया जाता है। 2021-22 में 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन अनुमानित है जो साल 2020-21 के 109.5 मिलियन टन से 1.82 मिलियन टन (18.02 लाख टन) ज्यादा है। खाद्यान के रिकॉर्ड उत्पादन का श्रेय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान, वैज्ञानिक और सरकार की नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, जो किसान भाइयों-बहनों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है। सरसों का बढ़ा रकबा। तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन बढ़ा 2021 में लोगों को खाद्य तेल कीमतों ने काफी परेशान किया।

किसानों ने दिखाई रुचि

इस साल तिलहन का भी रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सरसों, रेप सीड, मूंगफल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर सीड, अरंडी, तिल, अलसी को मिलाकर सभी 9 तिलहनों का उत्पादन 37.15 मिलियन टन होने का अनुमान है। जिसमें 11.46 मिलियन टन अकेले रेपसीड एवं सरसों है। ये भी एक रिकॉर्ड है। 2021 में 3200-3500 रुपए क्विंटल बिकी सरसों कुछ समय बाद में 7500-8000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गई है, जिसके बाद किसानों ने सरसों की बोवनी में काफी रुचि दिखाई है।

मोटे अनाज की बढ़ी मांग

पिछले कुछ वर्षों में मोटे अनाज, कदन्न (ज्वार, बाजरा, रागी, महुआ,सांवा, कोदो, कुटकी, कंगनी) की मांग तेजी से बढ़ी है। जिसके चलते किसानों को भी रुझान इन पोषण से भरपूर फसलों की तरफ गया है। 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में में कदन्न का 49.86 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। 2020-21 में 51.32 मिलिटन टन उत्पादन हुआ था, जबकि 2019-20 का उत्पादन 47.75 मिलियन टन था। मोटे तौर पर बात करें तो सरकार के लक्ष्य और साल 2020-21 के मुकाबले ज्वार, बाजरा और रागी का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि फाइनल नतीजे आना बाकी हैं।

चना का होगा रिकॉर्ड उत्पादन

दलहन की फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन चने का होता है। ये भी कह सकता है, जितना चना पैदा होता है, बाकी सब दलहनी फसलें मिलाकर उतना उत्पादन होता है। चने का इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। 2021-22 में 13.12 मिलियन टन का उत्पादन अनुमानित है। 2020-21 में 11.91, 2019-20 में 11.08 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। 2021-22 में अरहर का उत्पादन 4.00 मिलियन टन अनुमानित है। उड़द की बात करें तो रबी और खरीफ सीजन को मिलाकर 2.66 मिलियन टन का उत्पादन होने का अनुमान है। वहीं दोनों सीजन मिलाकर मूंग का उत्पादन 3.06 मिलियन टन होने का अनुमान है।

अगर मसूर की बात करें तो 1.58 मिलियन टन का उत्पादन अनुमानित है। 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 23.82 मिलियन टन से 3.14 मिलियन टन अधिक है।

सुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

जिले में जैविक खेती का रकबा निरंतर बढ़ता जा रहा

अंचल में बढ़ी जैविक खेती, कम लागत में हो रहा ज्यादा उत्पादन

अमित निगम, रतलाम।

जिले में जैविक खेती का रकबा निरंतर बढ़ता जा रहा है। शुद्ध खाद्यान्न और सब्जियों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जैविक खेती करने वाले किसानों को बेहतर मुनाफा मिलने लगा है, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है। कृषि विभाग भी रकबा बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। जिले में अभी करीब 3000 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता में कमी आने लगी है। प्राकृतिक अनुकूलन बिगड़ने से उत्पादन में कमी के साथ ही खेती की लागत भी बढ़ रही है। इसके चलते किसान भी जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिपलौदा विकासखंड के ग्राम रियावन निवासी कारूलाल धाकड़ ने बताया कि कृषि विभाग की सलाह पर उन्होंने जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। आठ हजार की लागत से आठ पक्के वर्मी कंपोस्ट बनाकर प्लास्टिक बेड लगाए। प्रति बेड लागत 1600 रुपए आई। प्रत्येक वर्मी कंपोस्ट बेड से आठ से 10 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जो तीन माह में तैयार हो जाता है। सोयाबीन तथा रबी में गेहूं की फसल में पूर्ण रूप से वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। इससे कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। वर्मी कंपोस्ट प्रति क्विंटल एक हजार रुपये के मान से मंदसौर, धार, उज्जैन, इंदौर तक भेजा जा रहा है।

केंचुआ खाद बनानी शुरू की

आदिवासी अंचल के किसान भी बड़ी संख्या में जैविक खेती की ओर आगे बढ़ चले हैं। सैलाना विकासखंड के ग्राम पंथवारी के आदिवासी किसान नागू सिंह ने बताया कि उनके पास लगभग दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। वे पहले कपास, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना आदि फसलें लेते थे। इनमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता था। इसके बाद वे आत्मा परियोजना से जुड़े। खेत में वर्मी पिट का निर्माण किया। केंचुआ खाद बनानी शुरू की। लगभग एक हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक खेतों में परिवर्तित कर लिया है। इससे उनकी खेती की लागत में 40 प्रतिशत की कमी आई।

सब्जी का ले रहे उत्पादन

नागूसिंह द्वारा जीवामृत, दशपर्णी, अर्क वेस्ट डी कंपोजर तथा अजोला यूनिट का निर्माण भी किया गया है, जिसका उपयोग जैविक खेती में किया जा रहा है। जैविक प्रशिक्षण प्राप्त कर आधा हेक्टेयर में गिल्की, तुरई, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर इत्यादि सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। जैविक सब्जी उत्पादन से नागू सिंह को 50 से 60 हजार की अतिरिक्त आमदनी मिल रही है।

किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती के लिए विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के साथ ही शासन की योजनाओं में मदद भी दी जाती है। इससे जैविक खेती का रकबा बढ़ने लगा है।

विजय चौरसिया, उप संचालक, कृषि कल्याण

नाबार्ड अराइज फाउंडेशन के माध्यम से सिखाएगा

अब किसान सीखेंगे आलू का बीज तैयार करना

» ग्वालियर के किसान खुद ही बीज तैयारकर पाएंगे

ग्वालियर। ग्वालियर जिले के किसान अब आलू का बीज तैयार करना सीखेंगे। जिससे वह उच्छ क्वालिटी के आलू का बीज तैयार कर मुनाफ कमाएंगे और अपनी आय को दो गुना करेंगे। इसके लिए नाबार्ड ने उटीला के दस गांव में बीज तैयार करने के लिए आलू मूल्य श्रंखला का शुभारंभ कर दिया हैं। इस योजना के अंतग्रत दस गांव में आलू के बीज तैयार किए जाएंगे। आलू का बीज तैयार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे किसान आलू के बीज तैयार करने में सक्षम हो सकें। जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इस कार्य में नाबार्ड ने अराइज फाउंडेशन को इसके लिए चुना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान,उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार एवं कृषि विवि इसमें टेक्नीकल मार्गदर्शन देगी। इस योजना के अंतर्गत एक फॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ भी बनाया जाएगा।

किसान लगाएंगे यूनिट- योजना के अंतर्गत मप्र सरकार के उद्यानिकी विभाग नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और अन्य सरकारी योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से काम किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में के तहत ग्वालियर जिले को प्रदेश सरकार द्वारा आलू उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। आलू से निर्मित होने वाले प्रोडक्ट अब किसान खुद तैयार करेंगे। इसकी यूनिट लगाएंगे और उसके लिए फंड की उपलब्धता नाबार्ड कराएगा।

बाजार से नहीं खरीदेंगे बीज

किसान अपने खेत में आलू पैदा कर उसके प्रोडक्ट तैयार करेंगे और बाजार में उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। जहां किसानों की आय बढ़ेगी वहीं रोजगार के अवसर पैदा होगें। किसानों की अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा। किसान जब खुद का उत्पाद पैक कर बेचेंगे तो आमजन को भी सस्ते दाम पर मिलेंगे। जिससे सभी को लाभ होगा। अभी किसान आलू के बीज खुद तैयार नहीं करते। बल्कि बाजार से खरीदते हैं। जब किसान स्वयं बीज तैयार करेंगे तो उन्हें बचत भी होगी।

एक करोड़ की टिश्यू कल्चर लैब 20 लाख में कैसे बनेगी

ग्वालियर में टिश्यू कल्चर लैब बनाने में फंड का रोड़ा

राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने भी की थी घोषणा

दिव्या मिश्रा, ग्वालियर।

देशभर के केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्रों में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित हैं, लेकिन मप्र में यह सपना टूट गया है। प्रदेश के इकलौते आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में टिश्यू कल्चर लैब बनाने की तैयारी चल रही थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे प्रस्तावित किया था। 20 लाख बजट भी आ चुका था। इसके बाद परिषद ने जानकारी भेजी कि बीस लाख के बजट में ही इसे तैयार करना होगा। वहीं जानकारों के मुताबिक इतने बजट में इसे बनाना संभव नहीं है, इसके लिए एक करोड़ रुपए चाहिए। यह लैब पूरे प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होती, लेकिन फिलहाल उम्मीदों पर पानी फिर गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मप्र को फायदा देने टिश्यू कल्चर लैब का प्रस्ताव लाया गया था। हाल ही में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने सीपीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनाया। विभाग ने करीब 73 लाख रुपए खर्च का एस्टीमेट बनाकर दिया। अब बजट न होने से टिश्यू कल्चर लैब का निर्माण टल गया है। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने भी ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में टिश्यू कल्चर लैब बनाए जाने की घोषणा की थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के अनुसार देश के हर केंद्र में टिश्यू कल्चर लैब है, लेकिन अब यह ग्वालियर में नहीं बनेगी।

टिश्यू कल्चर लैब का काम

टिश्यू कल्चर लैब में स्वस्थ पौधे टेस्ट ट्यूब में तैयार किए जाते हैं। इसमें माइक्रो ट्यूबर और माइक्रो प्लांट पद्धति से किसी भी सीजन में वातानुकूलित हाल और नेट हाउस में यह काम किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता कि चार साल में तैयार होने वाला बीज तीन साल में हो जाता है।

बजट-संसाधन सब चाहिए

केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र को यहां टिश्यू कल्चर लैब के लिए अलग भवन, जिसमें उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण से लेकर वैज्ञानिकों की टीम भी लगेगी। इसके लिए 20 लाख का बजट बेहद कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बजट में लैब बनाना संभव नहीं हैं।

देश के सभी आलू अनुसंधान केंद्रों में टिश्यू कल्चर लैब है। ग्वालियर में भी यह प्रस्तावित की गई थी, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके लिए 20 लाख का ही बजट दे रहा है, जिसमें यह संभव नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी ने 73 लाख का एस्टीमेट दिया है, जबकि इसके लिए हमें एक करोड़ की राशि की जरूरत है।
डॉ. एसपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र,ग्वालियर

कुलपति ने किया कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी का भ्रमण

खेमराज मौर्य, शिवपुरी।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति प्रो.एस.के.राव, निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ.वाय.पी.सिंह एवं सह निदेशक अनुसंधान एवं प्रक्षेत्र डॉ.आई. एस. नरूका द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी पर भ्रमण किया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रदर्शन एवं परीक्षण इकाईयों- शेडनेट हाउस में स्ट्राबेरी परीक्षण, औषधीय एवं मसाला फसल चन्द्रसूर, धनिया, प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम चना प्रजाति आर.व्ही.जी. 202, सरसों उत्पादन प्रजाति गिरराज जल संरक्षण संरचनाएं वर्षभर एक ही खेत में हराचारा उत्पादन इकाई, अमरूद पौध उत्पादन संतती, फसल संग्रहालय, वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन, समन्वित कृषि प्रणाली इकाई इत्यादि का अवलोकन करते हुये केन्द्र पर चल रही गतिविधियों की जानकारी ली एवं आवश्यक सुधार हेतु उचित परामर्श भी दिये। केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.एस.पी.सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट किया गया तथा कुलपति द्वारा केन्द्र के लिए आवश्यक बताये गये सुझावों पर अमल कराये जाने का आश्वत किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.एम.के.भार्गव द्वारा जिले के परिपेक्ष्य में फसल विविधिता की प्रगति एवं संभावनाओं पर पॉवर पोइंट प्रजेनेटेंशन के माध्यम से जिले का परिदृश्य बतलाया गया। डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन के कार्यक्रम में जानकारी दी गई तथा डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन एवं लक्ष्य के बारे में बतलाया गया वैज्ञानिक डॉ.जे.सी.गुप्ता द्वारा शेडनेट हाउस में लिए जाने वाले उत्पादन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉ. ए.एल. बसेडिया द्वारा मूल्य संवर्धन के बारे में जिले की स्थिति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर केन्द्र के समस्त स्टाफ डॉ.एन.के. कुशवाहा तकनीकी अधिकारी, विजय प्रताप सिंह शोध सहायक, सतेन्द्र गुप्ता, कु.आरती बंसल एवं नीतू वर्मा भी उपस्थित रही।

किसानों के खाते में पहुंची 10 करोड़ 10 लाख 45074 की फसल क्षति राहत राशि

शिवपुरी के किसान राजकुमार जाटव से किया संवाद

शिवपुरी। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि-बारिश से प्रभावित 1 लाख 46 हज़ार से अधिक किसानों के खाते में 202.90 करोड़ की राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में राहत राशि पहुंचाई। शिवपुरी जिले में भी ओलावृष्टि बारिश के कारण हजारों किसान प्रभावित हुए। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशन में प्रशासन की टीम द्वारा सर्वे किया गया और ओलावृष्टि बारिश से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई, उन्हें चिन्हित किया गया। किसानों को फ्सल क्षति की राहत राशि अब उनके खाते में पहुंचाई गई है। शिवपुरी जिले के 8642 किसानों के खाते में 10 करोड़ 10 लाख 45074 रुपए की फ्सल क्षति की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की गई है।

एनआईसी कक्ष में मौजूद रहे हितग्राही

यहां शिवपुरी के एनआईसी कक्ष में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एडीएम उमेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर विजेंद्र यादव, एसडीएम कोलारस ब्रिज श्रीवास्तव सहित किसान हितग्राही मौजूद थे। एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने फ्सल क्षति की राशि किसानों को देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद के दौरान शिवपुरी जिले के किसान राजकुमार जाटव से भी संवाद किया और उनका हालचाल जाना। राजकुमार ने फ्सल क्षति की 19 हज़ार 50 रुपये की राहत राशि मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा एनआईसी कक्ष में मौजूद किसान रामप्रकाश धाकड़ ने भी 21 हजार 190 रुपये की राहत राशि मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना की।

दूसरे राज्यों में बढ़ी बैतूल के जैविक गेहूं चावल की मांग

-जैविक उत्पादों से चौधरी को हो रही 7 लाख वार्षिक आय

भोपाल। बैतूल जिले के गाँव सोहागपुर के किसान स्वदेश चौधरी, जैविक खेती अपनाने वाले जिले के किसानों में प्रमुख हैं। वे अपनी 25 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ में गेहूं, चावल, धनिया, तूअर, मटर, चना, मेथी और लहसुन की जैविक खेती कर रहे हैं। स्थानीय बाजार के साथ उनका जैविक गेहूं और चावल छत्तीसगढ़ के रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थाई ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के कारण स्वदेश चौधरी के जैविक उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। चौधरी बताते हैं कि वे पिछले 12 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। उनके जैविक उत्पाद मप्र राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल से पंजीकृत हैं। पांच एकड़ जमीन में से वे साढ़ चार एकड़ में गेहूं, चावल और मूंगफली की फसल और शेष आधे एकड़ में जैविक धनिया, तूअर, मटर, चना, मेथी और लहसुन उगाते हैं। उन्हें रबी सीजन में लगभग 50 क्विंटल गेहूं और खरीफ सीजन में इतना ही चावल मिल जाता हैं। मानव स्वास्थ्य के अनुकूल जैविक उत्पादों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसमें लाभ भी अच्छा मिल जाता है। इसलिए स्वदेश चौधरी जैविक खेती और जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

-करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई थी सर्वसुविधा युक्त

बालाघाट की हाईटेक कृषि उपज मंडी का किसानों का नहीं मिल रहा लाभ

रफी अहमद अंसारी

बालाघाट। जिले के किसानों को एक छत के नीचे ही सर्वसुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से स्थानीय इतवारी बाजार में करोड़ो की लागत से हाईटेक कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया है, जो कि 2020 में ही पूर्ण हो चुका है और ठेकेदार द्वारा इसे सौंप भी दिया गया है। बावजूद इसके कृषि उपज मंडी का संचालन नहीं किए जाने से सर्वसुविधा युक्त उपज मंडी किसानों के काम नहीं आ रही है। जिसका खामियाजा आसपास के रहवासियों के साथ ही व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदारों के इस ओर ध्यान न देने से ये स्थिति और भी गंभीर बनती जा रही है।

आठ करोड़ 90 लाख की लागत से बनी मंडी- फल व सब्जी बेचने वाले किसान समेत अन्य किसानों को वाताअनुकूलित माहौल में व्यापार कर अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से 8 करोड़ 90 लाख की लागत से हाईटेक कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया है। साथ ही इस मंडी में कैंटीन समेत समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जिससे की मंडी में आने वाले किसान व व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो लेकिन मंडी तैयारी होने के एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंडी का संचालन शुरू नहीं किया जा सका है। हाईटेक कृषि उपज मंडी का संचालन न हो पाने के कारण इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

दुकानों का नहीं हुआ आवंटन

हाईटेक कृषि उपज मंडी में दुकानों को भी बनाया गया है जिससे के की जरुरतमंद इन दुकानों को लेकर अपना रोजगार कर सके, लेकिन दुकानों का आवंटन अब तक नहीं हो पाया है बावजूद इसके कुछ लोगों के द्वारा अवैध रुप से दुकानों में कब्जा कर लिया गया है और अवैध रुप से दुकानों का संचालन किया जा रहा है जिससे भी मंडी को नुकसान पहुंच रहा है।

-सेंट्रल जेल में पल रहीं पौने चार सौ गाय और दो सौ बछड़े

केंद्रीय जेल भोपाल में नगर निगम की छोड़ी गायों का हो रहा पालन और दूध से सुधर रही कैदियों की सेहत

-गौ-सेवा में केंद्रीय जेल प्रशासन मध्यप्रदेश में बना उदाहरण

अरविंद मिश्र। भोपाल

गाय हमारी माता है। अगर मां से दूध न मिले तो गाय मां का धर्म निभाती है। गाय समान रूप से सभी का पालन करती है। केंद्रीय जेल भोपाल में गाय सार्थकता प्रदान कर रही हैं। यहां सवाल तो इस बात का उठ रहा है कि जिस काम को नगर निगम भोपाल करके धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष प्राप्त कर सकता था, लेकिन निगम का काम जेल प्रशासन बखूबी निभा रहा है। सजायाफ्ता व खूंखार कैदियों को जेल प्रशासन ने अब धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष से जोड़ दिया है। नगर निगम की छोड़ी गायों की कैदी सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय जेल का बीमार कैदी-बंदी गाय के दूध से सेहत बना रहा है। जहां गाय कैदियों का 'कैल्शियम' बढ़ा रही हैं। गायों के दूध से कैदियों का पोषण के साथ गौसेवा भी हो रही है। सबसे बड़ी बिडंवना यह है कि जिन्हें पाप-कर्म के तहत कैद किया गया है, वही गौ-सेवा में लग गए हैं। जिस स्वच्छ समाज की उम्मीद की जानी चाहिए उसे बंदी जेल से ही पूरा कर रहे हैं। खास बात यह है कि भोपाल नगर निगम गायों को आवारा मवेशी के रूप में पकड़कर जेल की गौशाला में भेज रहा है। वहीं बूढ़ी-बीमार और घायल गायों की सेवा कर उन्हें तैयार कर दूध ही नहीं, गोबर का भी उपयोग करते हुए सनातन संस्कृति और धर्म का पालन कर रहा है। केंद्रीय जेल प्रशासन का यह कार्य जेल की चारदीवारी से बाहर अब प्रदेशभर के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। दरअसल, केंद्रीय जेल भोपाल में दस नबंवर 2007 से श्रीकृष्णा गौशाला संचालित है। यहां नगर निगम द्वारा पकड़ी गई आवारा और दूध नहीं देने वाली गाय छोड़ दी जाती हैं, जिनका भरण-पोषण केंद्रीय जेल प्रबंधन कर रहा है। अब वही बूढ़ी और आवारा गाय दूधारू हो गई हैं। जेल प्रबंधन की मेहनत और गौसेवा से यह सब संभव हुआ है। गायों की गोबर से जहां बड़ी मात्रा में गौ-काष्ट भी तैयार किया जा रहा है, वहीं इसका उपयोग विश्राम घाट से लेकर हवन-पूजन तक किया जा रहा है।

शासन से मिल रहा 20 रुपए प्रति गाय| केंद्रीय जेल प्रबंधन को शासन से गायों के भरण-पोषण के लिए 20 रुपए प्रति गाय के मान से राशि दी जा रही है। शासन से मिले अनुदान की 60 प्रतिशत राशि में दलिया, चूनी और खली दिया दिया जाता है। शेष राशि केंद्रीय जेल प्रबंधन को दी जाती है।

जेल में पल रहीं पौने चार सौ गाय

फिलहाल केंद्रीय जेल भोपाल में पौने चार सौ गाय पल रही हैं। जिसमें 70 गाय दूधारू हैं। इन गायों से 125 से 150 लीटर तक दूध उत्पादन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दूध का उपयोग सिर्फ कैदियों के लिए हो रहा है। हालांकि, जरूरत 350 लीटर से ज्यादा दूध की रहती है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बाजार से भी पैकेट का दूध मंगवाया जाता है।

जेल में दो सौ बछड़े तैयार

केंद्रीय जेल में पल रहीं अधिकांश गाय देशी नस्ल की हैं। जहां दो सौ से ज्यादा देशी बछड़े भी तैयार हो गए हैं। अब जेल प्रबंधन गायों के नस्ल सुधार के लिए दो सांड़ भी खरीदे हैं। जिसमें एक गिर और दूसरा साहीवाल नस्ल का है। वहीं प्रबंधन का अब फोकस है कि यहां तैयार हो रही गायों का गिर और साहीवाल का सीमन कराया जाएगा। ताकि इन दोनों नस्लों की ही बछिया तैयार हों। केंद्रीय जेल भोपाल में अभी 3,760 कैदी सजा काट रहे हैं। इसमें महिला-पुरुष दोनों हैं।

10 एकड़ में फैली गौशाला

जेल प्रबंधन ने गायों की संख्या को देखते हुए 10 एकड़ तक गौशाला का विस्तार किया है। इसके अलावा 12 एकड़ में तालाब का निर्माण कराया है। इससे गायों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसी तरह गायों के आहार के लिए 12-15 एकड़ में हरा चारा भी तैयार किया जाता है। हरा चारा प्रतिदिन गयों को दिया जाता है। साथ ही अप्रैल-मई में गेहूं का भूसा भी खरीदा जाता है।

जो गाय नगर निगम शहर से पकड़ता है, उन्हें हमारे यहां छोड़ा जाता है। जिन्हें हम तैयार करते हैं। गायों से प्राप्त दूध का उपयोग कैदियों के लिए किया जा रहा है। अब गायों की नस्ल सुधारने के लिए दो सांड़ एक गिर और एक साहीवाल को मंगवाया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि गायों का सीमन गिर व साहीवाल प्रजाति का करारया जाए। ताकि गायों का कुनबा बढ़ सके। हमारे यहां गौ-काष्ठ भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में गोबर से सीएनजी उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। **दिनेश नरगावे, जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, भोपाल**

सीएम शिवराज बोले-मध्यप्रदेश सरकार किसानों की सरकार

बाइस माह में किसानों को मिली पौने दो लाख करोड़ रुपए राहत

- मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 202 करोड़ की राहत राशि डाली
- निवाड़ी जिले के किसान की सामाजिक भूमिका की सराहना की
- सर्वे कार्य जल्दी करने के लिए राजस्व-प्रशासनिक अमले को बधाई

संवाददाता, भोपाल।

राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। संकट की स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़ जैसे संकट। किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बाद आवश्यक राहत देने में कभी देर नहीं की गई। गत जनवरी माह में ओलावृष्टि से प्रदेश के 26 जिलों में किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए 202 करोड़ 90 लाख की राशि एक लाख 46 हजार 101 किसानों के खाते में अंतरित की गई है। दो साल में किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण और अन्य सभी किसान-कल्याण योजनाओं में कुल पौने 2 लाख करोड़ किसानों को दिए गए हैं। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत राशि अंतरित करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधन के दौरान कही। इस दौरान प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं राजस्व विभाग मनीष रस्तोगी और राजस्व सचिव डॉ. संजय गोयल भी उपस्थित थे।

समय सीमा में हुआ फसल सर्वे

गत माह ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के बाद राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और अन्य विभागों के सहयोग से समय-सीमा में सर्वे कार्य हुआ। ग्रामों में प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई। प्रत्येक प्रभावित किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की गई। इन सब कार्यों के लिए सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, जन-प्रतिनिधि, किसान भाई-बहन और समाजसेवी बधाई के पात्र हैं। मध्यप्रदेश सरकार किसान के सुख-दुख में सदैव साथ रहेगी। किसानों सहित सभी वर्गों को जरूरत पर जरूरी मदद देकर उनका हौसला बढ़ाना सरकार का दायित्व है। इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

एक हजार ग्रामों में हुई थी ओलावृष्टि

प्रदेश के 1074 ग्रामों में ओलावृष्टि से और असामयिक वर्षा से एक लाख 34 हजार 19 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को क्षति हुई थी। प्रभावित जिलों में रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, धार, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बैतूल, हरदा, सतना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम और खंडवा शामिल हैं। जिलेवार राहत राशि प्रभावितों को देने का कार्य प्राथमिकता से किया गया।

ओले धरती पर नहीं मानो सीने पर गिरे हों

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब असमय वर्षा और ओलावृष्टि हुई, तब यही अनुभूति हुई थी कि ओले धरती पर या खेतों पर नहीं गिरे मानो उनके सीने पर गिरे हों। ऐसी घटनाएं विचलित करती हैं। किसानों को राहत देने के लिए तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर क्षति का जायजा लेने और सर्वे का कार्य किया गया। सर्वे कार्य भी ईमानदारी से हुआ। किसान भी इस प्रक्रिया से संतुष्ट रहें। गत सप्ताह खरीफ 2020 और रबी 2021 के लिए 45 लाख से अधिक किसानों के खातों में बीमा राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। फसल बीमा दावा के भुगतान की कुल 7 हजार 669 करोड़ राशि में से अब तक 5 हजार 660 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

संकट में किसानों के साथ सरकार- राजस्व मंत्री

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। संकट में किसानों के दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से फसल क्षति होने के संकट को तत्काल अपने संज्ञान में लेकर फसलों का सर्वे कराया। ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से चर्चा की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 7 हजार 618 करोड़ की राशि प्रदेश के किसानों को एक क्लिक से उपलब्ध कराई थी।

ग्वालियर में काजू-बादाम से 50 गुना महंगा मशरूम

ग्वालियर। पहले प्रोफेसर फिर निजी कॉलेज में प्रिंसिपल बने। 10 साल जॉब करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मशरूम की खेती के लिए वियतनाम जाकर ट्रेनिंग ली। इसके बाद घर में ही कोर्डीशेप (कीडाजड़ी) वैरायटी का मशरूम उगाना शुरू किया। महज 500 वर्गफीट में खेती से सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यह शख्स हैं महलगांव निवासी डॉ. एचएस गोस्वामी। गोस्वामी ने बताया कि 2018 से मशरूम उगा रहे हैं। हर माह एक लाख रुपए तक इससे कमा लेते हैं। वे मशरूम से जुड़े 48 प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए!

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
रहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)